

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1618/2010/अलवर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, कोटा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स विजय सोलवेक्स लिमिटेड,
अलवर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.11.2015

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 72/236/आरवैट/2008-09/10-11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 17.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, कोटा के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 1,20,985/- को अपास्त किया है।


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 06.12.2008 को चेकिंग के दौरान अनन्तपुरा, कोटा में वाहन संख्या एम.पी.-09-एचएफ-2614 को रोक कर चेक किया। वक्त चेकिंग वाहन में रिफाईण्ड पाम ऑयल विल्लीपलयम (तमिलनाडू) से अलवर के लिए परिवहनित किया जाना था, जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर कांटा पर्ची क्रमांक-निल दिनांक 01.12.08, जी आर नम्बर 411 दिनांक 01.12.08, मैसर्स यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की मैरीन कार्गो स्पेशिक वॉयेज पॉलिसी की छाया प्रति, वैट इनवॉयस संख्या 2029 दिनांक 01.12.08 एवं तमिलनाडू सरदार का फार्म जे.के. क्रमांक 1347 आदि दस्तावेज पेश किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर दस्तोवजों के साथ घोषणा पत्र वैट-47 पेश नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने राज्य के बाहर से बिना विधिक घोषणा पत्र वैट-47 के माल आयात किये जाने पर अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए करापवंचन के सन्देह में अधिनियम की धारा 76 (5)(ए) के अन्तर्गत वाहन को मय माल निरुद्ध किया गया। निरुद्ध आदेश की पालना में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त माल प्रत्यर्थी का है तथा आगामी कार्यवाही हेतु उसे पार्टी बनाया जाये, जिसे कर

निर्धारण अधिकारी ने स्वीकार करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया । नोटिस की पालना में जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि वित्त सचिव के पत्रांक एफ.12.(15)/वित्त/कर/2008/पार्ट-3 दिनांक 30.08.2008 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लेने तक ऐसी वस्तुओं के अन्तर्राज्जीय परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट-47/49 साथ में नहीं होने पर भी शास्ति आरोपित नहीं की जावे तथा जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 2775166 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब को अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53(1) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए माल की कीमत रु. 4,03,282/- पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,20,985/-आरोपित कर दी। उक्त आरोपित शास्ति से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में अपील स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2011 पारित किया,जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 06.12.2008 को वाहन की जांच पर वाहन में लदे माल के साथ वक्त चेकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 नहीं होने से अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी करने पर, जवाब के साथ वैट-47 नम्बर 2775166 प्रस्तुत किया गया। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने कर चोरी की मंशा से माल का परिवहन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 76(2)सपठित नियम 53(1) का उल्लंघन तथा कर चोरी की दोषी मानसिकता मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,20,985/-आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग पाया गया माल राज्य के बाहर से बिना विधिक घोषणा पत्र वैट-47 के परिवहन किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है, जिसके माल के साथ नहीं होने के कारण आरोपित शास्ति उचित है किन्तु अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के

कारण अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाये। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति नैसर्गिक न्याय के विस्द्ध के विपरीत होने के कारण अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रिफाईण्ड पाम ऑयल का आयात सी फार्म पर विल्लीपलयम (तमिलनाडू) से किया गया था, जिसके साथ वक्त परिहवन सभी आवश्यक दस्तावेज यथा-बिल,बिल्टी, कांटा पर्ची एवं तमिलनाडू सरकार का फार्म जेजे क्रमांक 1347 संलग्न थे, जिन्हें किसी भी जांच के द्वारा मिथ्या अथवा बोगस प्रमाणित नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में वित्त सचिव के पत्रांक एफ.12.(15)/ वित्त/कर/2008/पार्ट-3 दिनांक 30.08.2008 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लेने तक ऐसी वस्तुओं के अन्तर्राज्जीय परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट-47/49 साथ में नहीं होने पर भी शास्ति आरोपित नहीं की जावे तथा जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 2775166 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने उक्त कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,घट-प्रथम, वृत पाली बनाम मैसर्स देव आदित्य सेल्स कारपोरेशन,जयपुर (अपील संख्या 1147/2009/जयपुर) के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2010 का हवाला देते हुए बताया कि कर बोर्ड के उक्त निर्णय के आधार पर राजस्व की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत ठहराया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त निर्देश जांच तिथि तक वापस नहीं लिये गये थे। उन्होंने उक्त कथन के साथ उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट-2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा एवं अन्य 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित निर्णयों को आधार बनाते हुए अभिवाक् किया कि उक्त दोनों निर्णयों में



राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में जो सिद्धान्त अवधारित किया है कि वह इस प्रकरण में भी पूर्णतः लागू होते हैं। हस्तगत अपील उक्त निर्णय से आच्छादित होने के कारण प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में वित्त सचिव के पत्रांक एफ.12.(15)/ वित्त/कर/2008/पार्ट-3 दिनांक 30.08.2008 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लेने तक ऐसी वस्तुओं के अन्तर्राज्जीय परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट-47/49 साथ में नहीं होने पर भी शास्ति आरोपित नहीं की जावे। वित्त सचिव के पत्रांक एफ.12.(15)/ वित्त/कर/2008/पार्ट-3 दिनांक 30.08.2008 द्वारा जारी राज्य सरकार के उक्त निर्देश जांच तिथि अर्थात् दिनांक 22.02.2009 में प्रचलित थे क्योंकि उक्त निर्देश दिनांक 27.02.2009 को वापस लिये गये हैं और जांच कार्यवाही 06.12.2008 को सम्पादित की गई है, इसलिए उक्त निर्देशों के तहत वैट-47 के अभाव में शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं है। इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण कर अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को अपास्त किया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नम्बर 2775166 प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मैसर्स डी.पी.मेटल्स में प्रातिपादित सिद्धान्त के अनुसार शास्ति आरोपीय नहीं है।

उक्त सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार किया जाना समीचीन होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेटे वाल्यूम 35 पार्ट-2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the

transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है।

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने राज्य सरकार के निर्देश, न्यायिक दृष्टान्तों तथा प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप का औचित्य यह पीठ अनुभव नहीं करती है। फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य